

प्रेषक,

आर०डी० पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 11 अप्रैल, 2008

विषय : मा० उच्च न्यायालय के अधिष्ठान के उप निबन्धक एवं उप निबन्धक से प्रोन्नत होने वाले संयुक्त निबन्धक पद के वेतनमानों का संशोधन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 4095/1-ए-14/एडमिन-ए/2007 दिनांक 21 सितम्बर, 2007 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में कार्यरत उप निबन्धकों का अपने वेतनमान में संशोधन सम्बन्धी प्रत्यावेदन (उत्तर प्रदेश शासन के न्याय विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या : अधि०-ए-3435/सात-न्याय-1-2005-69/90 दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 एवं उत्तरांचल शासन के सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 3518/XXX(I)/2004-62(5)/2004 दिनांक 7 नवम्बर, 2004 की प्रतिलिपि सहित) शासन के विचारार्थ प्रेषित किया गया था।

2- उप निबन्धकों द्वारा अपने उक्त प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि उ०प्र० शासन ने अपने उक्त शासनादेश दिनांक 18.10.2005 द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिष्ठान के उप निबन्धक पद का वेतनमान रु. 10,650-15,850 से बढ़ाकर रु. 12000-16,500 कर दिया गया है तथा उत्तराखण्ड सचिवालय में भी उप- सचिव पद का वेतनमान पुनरीक्षित कर रु. 12000-16500 कर दिया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि शासन के उप सचिव पद का कार्य एवं उप निबन्धक पद के कार्य की प्रकृति समान है, अतः इन सब आधारों पर अनुरोध किया गया है कि उप निबन्धक पद का वेतनमान संशोधित कर रु. 10650-15850 के स्थान पर रु. 12000-16500 कर दिया जाय।

3- शासन द्वारा मामले में सम्यक विचार किया गया। इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया कि उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 18.10.2005 द्वारा संयुक्त निबन्धक के पद का वेतनमान रु. 12000-16500 से उच्चिकृत कर रु. 14300-18300 कर दिया गया है एवं शासन में भी उप सचिव पद से प्रोन्नत होने वाले संयुक्त सचिव पद का वेतनमान रु. 14300-400-18300 है।

4- अतः मा० उच्च न्यायालय के अधिष्ठान के उक्त पदों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु शासन स्तर पर गठित वेतन विसंगति समिति (विशेषज्ञ समिति) की संस्तुति के दृष्टिगत वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 141/XXVII(7)/दसवीं बै० न्याय वि०/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008

के क्रम में उप निबन्धक पद के रु. 10650-15850 के वेतनमान को दिनांक 18.10.2005 से उच्चीकृत कर रु. 12000-375-16500 करने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- मा0 उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में महानिबन्धक, अपर निबन्धक के दोनों पदों पर तथा संयुक्त निबन्धक के स्वीकृत तीन पदों में से दो पदों पर तैनात होने वाले न्यायिक सेवा के अधिकारी अपने मौलिक पद के अनुरूप वेतनमान प्राप्त करेंगे। संयुक्त निबन्धक के एक पद पर उप निबन्धक पद से संयुक्त निबन्धक पद पर पदोन्नति प्राप्त अधिकारी को दिनांक 17.10.2005 तक रु. 12000-375-16500 का वेतनमान अनुमन्य होगा तथा दिनांक 18.10.2005 से समिति की संस्तुतिनुसार रु.14300-400-18300 का वेतनमान अनुमन्य किये जाने की भी श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6- उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 234/न्याय अनुभाग/2001 दिनांक 2.5.2001 के क्रम में उप निबन्धक से पदोन्नति प्राप्त वर्तमान में कार्यरत संयुक्त निबन्धक का वेतनमान उच्चतर निर्धारित कर दिया गया है, अतः यदि पूर्व में कोई धनराशि उक्त पैरा-5 में निर्धारित वेतनमान से अधिक आहरित की गई हो, तब उसकी वसूली न की जाय एवं निर्धारित अधिक धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में दी गई समझी जाय। इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से वर्तमान में कार्यरत संयुक्त निबन्धक रु. 14300-400-18300 के वेतनमान में उक्त प्रस्तर-5 में निर्धारित वेतन आहरित करेंगे।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 1007/XXVII(7)/2008 दिनांक 9 अप्रैल, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0डी0 पालीवाल)
सचिव,

संख्या : 119/XXXVI(1)एक/2008-511/2007 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड जालनवाला, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 4- वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव।